भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1725
दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

फ़्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम

1725. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) इंडिया के अध्ययन के अनुसार भारत सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और भारत के ताप विद्युत संयंत्र धान की पराली जलाने की तुलना में 240 गुना अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता के कारण जन स्वास्थ्य पर इन ताप विद्युत संयंत्रों के प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में हुई हानि का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियां देश में कुल ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल 8 प्रतिशत में ही कार्य कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : सभी ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानदंडों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है। एमओईएफ और सीसी की अधिसूचना दिनांक 07.12.2015, 31.03.2021 और 05.09.2022 में श्रेणी-क, ख और ग के रूप में वर्गीकृत कोयला आधारित टीपीपी के संबंध में स्टैक उत्सर्जन मानदंड [सल्फर डाइ-ऑक्साइड (SO_2) सहित] और अनुपालन के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है।

SO_2 उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए, कोयला आधारित टीपीपी में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियां संस्थापित की जा रही हैं। टीपीपी में एफजीडी की संस्थापना के लिए कुल 537 यूनिट (2,04,160 मेगावाट) चिन्हित की गई हैं। इनमें से 44 यूनिटों (22,590 मेगावाट) में एफजीडी संस्थापित की जा चुकी है, 233 यूनिट (1,02,040 मेगावाट) में कॉन्ट्रेक्ट दिए जा चुके हैं/कार्यान्वयन के अधीन हैं, 138 यूनिट (43,987 मेगावाट) निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं और 122 यूनिट (35,543 मेगावाट) निविदा-पूर्व प्रक्रिया के अंतर्गत हैं।

****